



प्रकाश हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
युगलपीठ

न्यायपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं
माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायाधीश

विविध अपील (प्रतिकर) क्र. 1132/2010

अपीलकर्ता :

लगभग 50 वर्ष

1. माधो प्रसाद, पिता गंगा राम साहू, आयु

2. श्रीमती रामकुमारी, पति माधो प्रसाद साहू,
आयु लगभग 48 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम बनारी, थाना एवं तहसील

जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी :

1. पूर्णानंद, पिता बाबूलाल सूर्यवंशी, आयु लगभग 25 वर्ष,
निवासी बनारी, थाना एवं तहसील जांजगीर,
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) (चालक्र)

2. श्रीमती शांतिकुमारी, पति पुरुषोत्तमलाल साहू,
निवासी क्वार्टर क्रमांक 1/H-30, जोन-2, खुर्शीपार,
भिलाई।

3. बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
शाखा रायपुर द्वारा शाखा प्रबंधक, बजाज एलायंस
जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिला रायपुर (छ.ग.)।

मोटर यान अधिनियम क्री धारा 173 के तहत दायर विविध अपील

उपस्थित : सुश्री सोनिया कुलदीप, अपीलकर्ताओं की अधिवक्ता



श्री एस.एस. राजपूत एवं सुश्री रेनू सिंह, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के
अधिवक्ता

आदेश

दिनांक : 26 अगस्त, 2011

निम्न आदेश माननीय **मुख्य न्यायाधीश राजीव गुप्ता**, द्वारा पारित क्रिया
गया :

1. स्व. कु. शांता साहू के दुर्भाग्यशाली माता-पिता इस अपील में हमारे समक्ष
अपीलकर्ता हैं, जो कि दिनांक 22.07.2010 को पारित अधिनिर्णय, दावा प्रकरण
क्रमांक 29/2009 में अधीनस्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जांजगीर (संक्षेप
में 'अधिकरण') द्वारा अभिलिखित प्रतिकर राशि में वृद्धि हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलकर्ताओं/दावेदारों ने स्व. कु. शांता साहू की मृत्यु दिनांक 22.03.2009
को मोटर दुर्घटना में हो जाने के कारण, मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के
अंतर्गत दावा याचिका प्रस्तुत करते हुए, ₹11,00,000/- की प्रतिकर की मांग की
थी। इसके विरुद्ध, अधिकरण ने कुल ₹1,37,000/- की प्रतिकर राशि, तथा दावा
याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7% वार्षिक
ब्याज सहित प्रदान की।



3. प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दिया कि दावेदारों की पुत्री कु. शांता साहू की मृत्यु दिनांक 22.03.2009 को मोटर दुर्घटना में कारित चोटों के कारण हुई। दुर्घटना, अपघाती वाहन ट्रक क्रमांक C.G.-07C/2297 के चालक द्वारा उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चलाने के कारण घटित हुई। चूँकि उक्त वाहन ट्रक दुर्घटना की तिथि को बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमित था तथा बीमा कंपनी किसी भी प्रकार की पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन को सिद्ध नहीं कर सकी, अतः बीमा

कंपनी दावेदारों को प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी है।

4. चूँकि प्रत्यर्थी पक्ष ने अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अधिकरण द्वारा दर्ज उक्त निष्कर्ष अब अंतिम हो गए हैं।

5. अधिकरण ने मृतका की आय का आकलन मोटर यान अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट काल्पनिक आय के आधार पर ₹15,000/- वार्षिक निर्धारित क्रिया। ₹15,000/- में से मृतका के निजी खर्च हेतु 1/3 भाग घटाकर दावेदारों की निर्भरता ₹10,000/- वार्षिक आंकी गई। वार्षिक निर्भरता ₹10,000/- को 13 के गुणक से गुणा कर प्रतिकर राशि ₹1,30,000/-



निर्धारित की गई। अन्य मदों के अंतर्गत ₹7,000/- की अतिरिक्त राशि प्रदान कर, अधिकरण ने कुल ₹1,37,000/- प्रतिकर राशि, स्व. कु. शांता साहू की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए, दावेदारों को प्रदान की। अधिकरण ने यह भी निर्देशित किया कि ₹1,37,000/- की उपर्युक्त प्रतिकर राशि पर, दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक, 7% वार्षिक ब्याज अदा किया जाए।

6. अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सोनिया कुलदीप ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने मृतका की आय संबंधी दावेदारों के साक्ष्यों को स्वीकार न करते हुए त्रुटि की है और उसकी आय केवल ₹15,000/- वार्षिक ही मानी है; तथा केवल ₹1,37,000/- की न्यून प्रतिकर राशि प्रदान की है।

7. इसके विपरीत, श्री एस.एस. राजपूत एवं सुश्री रेनू सिंह, प्रत्यर्थी क्रमांक 3— बजाज एलायंस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड आपराधिक वाहन ट्रक के बीमाकर्ता के अधिवक्ता ने अधिकरण द्वारा प्रदान किए गए प्रतिकर का समर्थन



क्रिया तथा यह तर्क क्रिया क्रि ₹1,37,000/- की प्रतिक्रर राशि वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों में समुचित एवं न्यायोचित है।

8. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायालय/अधिकरण द्वारा प्रदान क्रिया जाने वाला प्रतिक्रर न्यायसंगत एवं उपयुक्त होना चाहिए। प्रतिक्रर की राशि न तो अत्यधिक अल्प होनी चाहिए और न ही किसी प्रकार का अवांछित लाभ प्रदान करने वाली होनी चाहिए।

9. अब हम यह परीक्षण करेंगे कि अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹1,37,000/- की प्रतिक्रर राशि क्या वर्तमान मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित एवं उचित है।

10. निस्संदेह, दावेदारों ने यह दावा क्रिया क्रि उनकी पुत्री, दिवंगत कु. संता साहू ब्यूटी पार्लर एवं क्रिराना दुक्रान चलाकर ₹6,000/- प्रतिमाह अर्जित करती थी, क्रिन्तु अधिकरण के समक्ष इस व्यवसाय अथवा ₹6,000/- प्रतिमाह आय के समर्थन में कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्रष्य प्रस्तुत नहीं क्रिया गया। अतः मृतक्रा



क्री आय संबंधी दावेदारों के कथन को अस्वीकार करने में अधिकरण के दृष्टिकोण में हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती।

11. तथापि, वर्ष 2009 में मोटर यान अधिनियम क्री धारा 163-क के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट काल्पनिक आय के आधार पर अधिकरण द्वारा मृतका क्री वार्षिक आय ₹15,000/- निर्धारित करना प्रतीत होता है तथा पुनर्विचार क्री आवश्यकता है।

12. धारा 163-क , जिसके अंतर्गत द्वितीय अनुसूची वर्ष 1994 में सम्मिलित क्री गई थी, का प्रावधान इस प्रकार है :

“[163-क . संरचित सूत्र के आधार पर प्रतिकर के भुगतान संबंधी विशेष

उपबंध.-

(1)

इस अधिनियम या वर्तमान में प्रवर्तन में किसी अन्य विधि या विधि के समान प्रभाव वाले किसी साधन में निहित किसी बात के होते हुए भी, मोटर



यान के स्वामी या अधिकृत बीमाकर्ता पर यह दायित्व होगा कि मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी अपंगता की दशा में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार, विधिक उत्तराधिकारियों अथवा पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर राशि का भुगतान करे।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “स्थायी अपंगता” का वही

अर्थ एवं सीमा होगी जो कि कार्य श्रमिक प्रतिकर अधिनियम, 1923 में निर्धारित है।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रतिकर के किसी दावे में, दावा करने वाले को

यह आरोपित या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी अपंगता के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है, वह वाहन के स्वामी अथवा संबंधित अन्य किसी व्यक्ति के किसी गलत कार्य, उपेक्षा या चूक के कारण हुई थी।





(3) केंद्रीय शासन, जीवन-निर्वाह की लागत को दृष्टिगत रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकेगा।”

13. उपर्युक्त उद्धृत धारा 163-क्र की उपधारा (3) के अनुसार केंद्रीय सरकार पर यह वैधानिक दायित्व था कि वह जीवन-निर्वाह की लागत को ध्यान में रखकर समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन करता।

14. किन्तु, धारा 163-क्र की उपधारा (3) में निहित प्रावधान के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची में आवश्यक संशोधन न किए जाने के कारण अधिनियम की धारा 163-क्र के उपधारा (3) के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने में केंद्रीय सरकार की विफलता के कारण, न्यायालय/अधिकरण इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि वर्ष 1994 (जब द्वितीय अनुसूची लागू हुई) से लेकर संबंधित प्रकरण में दुर्घटना की तिथि तक आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य तथा जीवन-निर्वाह की लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है।





15. अब वर्तमान प्रकरण पर लौटते हुए—वह दुर्भाग्यशाली दुर्घटना जिसमें दावेदारों की पुत्री कु. संता साहू ने वर्ष 2009 में अपनी जान गंवाई, थी। यदि वर्ष 1994 से वर्ष 2009 के मध्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य-वृद्धि तथा जीवन-निर्वाह लागत में वृद्धि को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट ₹15,000/- की काल्पनिक आय वर्ष 2009 में क्रम-से-क्रम ₹36,000/- प्रति वर्ष के बराबर होती। इसलिए, हम मृतका की काल्पनिक आय ₹36,000/- प्रतिवर्ष मानकर प्रतिकर का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रस्ताव रखते हैं।

16. चूँकि मृतका कु. संता साहू दुर्घटना की तिथि को अविवाहित थीं और दावेदार उनके माता-पिता हैं, अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा सैयद बसीर अहमद एवं अन्य बनाम मोहम्मद जमील एवं अन्य तथा श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य में प्रतिपादित विधि के आलोक में, मृतका की आय का 50% उसके व्यक्तिगत व्यय हेतु घटाया जाना उचित है। इस प्रकार, ₹36,000/- का 50% घटाने के बाद दावेदारों की वार्षिक निर्भरता राशि ₹18,000/- निर्धारित की जाती है।



17. चूँकि दावेदार मृतका के माता-पिता हैं, अतः इस प्रकरण में उपयुक्त गुणांक 10 से अधिक नहीं हो सकता ग्रेटर बम्बई महानगर पालिका बनाम लक्ष्मण अय्यर एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार, जिन मामलों में दावेदार मृतक के माता-पिता हों, वहाँ गुणांक 10 से अधिक नहीं होना चाहिए।

18. वार्षिक निर्भरता राशि ₹18,000/- को 10 के गुणांक से गुणा करने पर प्रतिकर राशि ₹1,80,000/- निर्धारित होती है। दावेदारगण को अंतिम संस्कार खर्च हेतु ₹5,000/- तथा संपत्ति की हानि हेतु ₹5,000/- और प्रदान किए जाने योग्य हैं। इस प्रकार, दावेदारगण अपनी पुत्री कु. संता साहू की मृत्यु के लिए कुल ₹1,90,000/- प्रतिकर राशि के हकदार बनते हैं।

19. पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण के समक्ष इस बात को लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो कि बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर दावेदार कितनी अवधि के लिए ब्याज पाने के अधिकारी होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर देय ब्याज की गणना इसी अपील में कर दी जाए।



20. सभी सुसंगत तथ्यों का विचार करते हुए—जिसमें दावा याचिका तथा वर्तमान अपील के निर्णय में हुई विलम्ब अवधि भी सम्मिलित है—और यह तथ्य भी कि सम्पूर्ण विलम्ब के लिए केवल बीमा कंपनी को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता, हम बढी हुई प्रतिकर राशि ₹63,000/- पर देय ब्याज की राशि ₹7,000/- निर्धारित करते हैं।

21. उपर्युक्त कारणों से, प्रतिकर में वृद्धि हेतु दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹1,37,000/- की प्रतिकर राशि को बढ़ाकर ₹1,90,000/- किया जाता है। बढी हुई प्रतिकर राशि ₹63,000/- पर देय ब्याज की परिमाणित राशि ₹7,000/- अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है।

22. प्रत्यर्थी क्रमांक 3 — बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड — को तीन माह की अवधि प्रदान की जाती है ताकि वह कुल राशि ₹70,000/-



(₹63,000/- बढी हुई प्रतिकर राशि +₹7,000/- बढी हुई प्रतिकर राशि पर परिमाणित ब्याज) संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष जमा कर सके।

23. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं क्रिया जा रहा है।

सही/-

मुख्यन्यायाधीश

सही/-

आर. एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पत्रकारों के सीमित प्रयोग हेतु क्रिया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं क्रिया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक - प्रशांत पारख, अधिवक्ता